amendments to clauses 2, 3 4 and 1. He is not going to move them. Now, I will put all the clauses together to vote.

*Clauses 2 to 13 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I beg to move:

'That the Bill be passed.'

*The question was put and the motion was adopted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: You got it in time.

SHRI JASWANT SINGH: Thank you, Madam.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We have completed it in time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have completed earlier than that. You wanted me to finish it by 4.15 p.m. So, we have enough time to pass the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2003.

---

**THE MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL, 2003.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI P.C. THOMAS): Madam Deputy Chairperson,

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it your first piloting of a marriage?

SHRI P.C. THOMAS: Maiden.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Maiden piloting of a Marriage Bill. That is very good. Naturally, a maiden has to pilot a marriage. A married person should not.

**श्री बालकवि बैरागी** (मध्य प्रदेश) : महोदया, यह मैरिज नही है, यह स्पैशल मैरिज है। विशेष विवाह है।

SHRI P.C. THOMAS: Madam, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954 and the Hindu Marriage Act, 1955, be taken into consideration."

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka) : Madam, I am on a point of order. The Minister should be kind enough to mention my name because the Bill was first introduced by me as a Private Member's Bill on 25th April and afterwards the Bill was taken up by the Government on 9th May. At least, I feel, he should be kind enough to mention my name.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will definitely do it. A marriage cannot be there without mentioning a lady's name.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: That is the first thing which I would like him to say and he should not forget it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When you make your statement, you can mention the name of the lady.

SHRI P.C. THOMAS: Madam, the name of the lady will be certainly mentioned.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Madam, the Bill is about divorce, not about marriage.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I read the title of the Bill. I don't read the content of it.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Divorce comes after marriage.

SHRI P.C. THOMAS: Madam, this Bill is meant for women. This Bill seeks to amend the provisions of the Special Marriage Act, 1954 and the Hindu Marriage Act, 1955. The provisions relate to certain reliefs which are sought under these Acts. The jurisdiction of the courts is laid down in section 31 of the Special Marriage Act and section 19 of the Hindu Marriage Act as (a) where the respondent resides or the couple last resided together or where the marriage was solemnised or where the petitioner herself can

go, that is, where the respondent is residing outside the territory where the jurisdiction of the Act goes; Or (b) the respondent, the husband, has not been heard of as being alive for seven years, which draws the natural presumption. This Bill provides for a petitioner, the wife, to move in the court at the place where she resides. That is the salient feature of the amendment Bill. This Section is sought to be amended. Section 31 of the Special Marriage Act, which is almost parallel to the provision in the Hindu Marriage Act, i.e., Section 19, is sought to be amended.

There is one small amendment with regard to the period of limitation given for an appeal. The existing provision gives 30 days for filing an appeal from the date of decree or order; whereas, this amendment Bill seeks that this period should be increased to 90 days. Though it is a small amendment Bill, but it will go a very long way so far as our women are concerned, so far as the women who are in hardships, especially when they are cruelly dealt with by their husbands, are concerned.

Of course, I would like to refer to the name of the hon. Member, Shrimati Bimba Raikar who comes from Karnataka. In fact, the Law Commission had also made a recommendation in this regard in its 178th Report. The National Commission for Women had also referred to the jurisdictional point in its report of 1999-2000. There is a Supreme Court judgement of January, 2000 where the Supreme Court stated that the period of 30 days was inadequate. The Supreme Court has also suggested that this period should be increased to 90 days. These are the main aspects of the Bill. Now, I commend this Bill for the consideration of the House.

*The question was proposed.*

SHRIMATI BIMBA RAIKAR : Madam, the dowry harassment cases are on the increase. A woman is treated badly at her husband's place by her in-laws. Hence, most of the marriages end in divorce.

As per the present laws, a victimised wife has to file a suit for divorce at the place of her husband's usual place of residence or wherever he is. A married woman usually does not establish contacts or goodwill at the place of her husband's residence. After separation, she lives in her own house at a place which may be far away from her husband's place. Now,

**4.00 P.M.**

in this situation, filing a divorce petition at the place of her husband's residence is not practical. She cannot go there every now and then on the hearing dates set by the court. Moreover, in a place where her husband resides, she cannot expect to have support or sympathy from anybody. She is thus put to a lot of inconvenience and disadvantages because she does not have money and she is taking care of her children also.

To overcome this difficulty for harassed women who file divorce suits, it is necessary to change the jurisdiction, that is, for filing a suit and the disposal of the case, to the place where the woman resides. This will help her and give support and protection to her and her family members. Madam, I hope the Government would do its best for harassed women and try to help our womenfolk.

**श्रीमती माया सिंह** (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदया, आज विवाह कानून मे संशोधन के लिए अधिनियम सम्माननीय सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत छोटा बिल है पर इसकी लघुता इसके महत्व को कम नही करती है। श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व मे वर्तमान सरकार ने समस्त कानूनो को महिलाओ के हितो के अनुरूप बनाने का बीड़ा उठाय. है। सरकार ने महिला हितो से संबंधित विषयो पर जो संवदेनशीलता एवं सक्रियता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। विचारार्थ विधेयक का पहला भाग राष्ट्रीय महिला आयोग एवं विधि आयोग की अनुशंसा पर आधारित है और दूसरा भाग सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर आधारित है। इन संवैधानिक संस्थाओ की अनुशंसाओ के आधार पर कानून मे संशोधन के लिए अधिनियम पारित कराने की सरकार की पहल निश्चय ही स्वागत योग्य है। प्रस्तावित अधिनियम का प्रथम उद्देश्य वर्तमान कानून की एक कमी को दूर करना है। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी। मान लीजिए, कोई लड़की ग्वालियर की रहने वाली है और उसकी शादी कोलकाता मे रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ होती है। शादी के बाद वह अपने पति के साथ बंगलौर रहने चली जाती है। कुछ माह के बाद पति के साथ अनबन हो जाए, चाहे किन्हीं कारणों से भी हो, दहेज के कारण या अन्य किसी कारण से वह सताई जाती है और कुछ माह के बाद वह वापस अपनी मां के पास रहने ग्वालियर आ जाती है। अगर उसे न्यायालय मे विवाह से संबंधित कोई केस या कोई प्रार्थना करनी हो तो उसे या तो कोलकाता जाना होगा या बंगलोर क्योंकि कोलकाता मे उसकी शादी हुई और बंगलौर मे उसका पति रहता है। वर्तमान कानून के अनुसार वह ग्वालियर न्यायालय का दरवाजा नही खटखटा सकती। स्पष्ट है कि इससे कई महिलाओ को बहुत पीड़ा, परेशानी और कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा था। प्रस्तावित विधेयक विवाहित महिला को यह अधिकार देता है कि वह जहां रह रही है वही पर न्यायिक आदेश से तलाक या अलग रहने से संबंधित मुकदमा दायर कर सकती है। वह जहां रह रही है उसी स्थान से केस कर सकती है।

प्रस्तावित विधेयक का दूसरा भाग अपील से संबंधित है। इस बिल मे अपील की अवधि तीस दिन से बढ़ाकर नब्बे दिन की है। कई बार यह देखा गया है कि पुरुष धोखे से या महिला की अज्ञानता का लाभ उठाकर कोई न्यायिक आदेश प्राप्त कर लेते हैं। इससे पहले कि महिला सतर्क हो, वह वकील का सहारा लेकर उच्च न्यायालय तक पहुंचे, तीस दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और वह अपने अपील के अधिकार से वंचित हो जाती है। प्रस्तावित संशोधन से इस अन्यायपूर्ण स्थिति पर रोक लगेगी। यह दूसरा कदम भी बहुत स्वागत योग्य है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक को सम्माननीय सदन के सभी दलो का पूर्ण समर्थन मिलेगा और यह जो पहल सरकार ने की है, विधि मंत्री जो यह प्रस्तावित बिल संशोधन के लिए लेकर आए हैं उससे हमारे देश की तमाम ऐसी महिलाएं जो कि इस दुख और तकलीफ को सह रही हैं; उन्हे इससे बहुत सहारा मिलेगा, उनकी पीड़ा कम होगी इसलिए मेरी सदन से अपील है कि इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन दे। धन्यवाद।

**श्रीमती चन्द्रकला पांडे** (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, मेरे पूर्व वक्ताओ ने विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में जो संशोधन लाए गए हैं उनके बारे में उदाहरणसहित बहुत ही विस्तार से बताया। मैं भी इसका समर्थन करना चाहूंगी क्योकि इससे जो पीड़ित महिला है उसे कम से कम थोड़ी-बहुत सहूलियत जरूर प्राप्त होगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि महिला संगठनों और आंदोलनों आदि ने भी महिलाओं के क्षेत्र मे जो पुराना उपबंध था, उसे यथेष्ट और समुचित नही पाया था। मौजूद उपबंध के तहत कोई पीड़ित पत्नी ऐसे जिला न्यायालय में अपनी अर्जी फाइल नहीं कर सकती थी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में वह निवास करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जो सामान्य संशोधन लाए गए हैं वे स्वागत योग्य हैं। उनका मैं समर्थन करती हूं। वैसे इन दिनो नाना बहानो से भले ही महिला आरक्षण विधेयक को टालने की ही नही, गला घोट कर मार डालने की कोशिश जारी है। पर सरकार ने जो दो बूंद राहत तलाक लेने वाली पीड़ित महिला को देने की चेष्टा की है उनके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और इन संशोधनो का समर्थन भी करती हूं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की क्रमशः धारा 31 और धारा 19 मे प्रस्तावित यह संशोधन भारत के विधि आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशो पर भी आधारित है और देश के प्रायः सभी महिला संगठनों ने इसका समर्थन किया है।

दूसरा संशोधन हाल ही मे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय मे संप्रेक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी वैवाहिक याद के पक्षकार 30 दिन की अवधि के स्थान पर 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकेंगे। मैं मानती हूं दोनो संशोधन व्यवहारिक स्तर पर पीड़ित स्त्री को न्याय दिला सकेगे।

इस संदर्भ मे मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगी। मैडम, भले ही शास्त्रो मे "यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" और साहित्य मे दो-दो मात्राएं लेकर नर से आगे है नारी - की अनुगूंज हो, भले ही अंग्रेजी के man शब्द से woman शब्द में दो अक्षर ज्यादा हो, भले ही वह घर की स्वामिनी होने के कारण घरनी, गृह की मालकिन होने के कारण गृहिणी और महलो की अधिष्ठात्री होने के कारण महिला कहलाए और भले ही लोक जीवन में "बिन घरनी घर भूत का

डेरा" जैसी कहावतें प्रचलित हों और यह भी सच हो कि रेत, ईंट और सुर्खी से बने मकान को स्त्री ही घर बनाती हो, पर यह भी सच है कि उसके ये सारे विशेषण, सारे पदनाम पति से जुड़ कर हैं। उसका अपना कहीं कोई घर नहीं होता। विवाह के पहले वह पिता के घर में पराई बनी रहती है, लोग कहते हैं पराए घर जाने वाली है। विवाह के बाद पति के घर में पराई होती, लोग कहते हैं कि पराए घर से आई है। वह घर की सामग्रियों में शामिल हो सब की स्वामिनी तो कहलाने लगती है, पर दरअसल उसकी स्थिति "केयर टेकर" की ही बनी रहती है। मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह एक ऐसा कंप्रीहैंसिव बिल लाएं जिसमे ज्वाइंट मैट्रीमोनियल राइट की सुनिश्चितता हो और जिससे पति से संबंध विच्छेद की बात होते ही उसे घर से यह कह कर न निकाल दिया जाए कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नही।

हिन्दू विवाह पद्धति मे सप्तपदी के मंत्र जो विवाह की पूर्णता और वैधत्व पर अंतेम मुहर लगाते हैं, प्रति पग पर यही दुहर बातें हैं, पत्नी पति की आज्ञाकारिणी बने, अनुवर्तिनी बने और उसके पुत्रों की माता बने। वह अपने पति को 10 पुत्र दे, उसे एक से ग्यारह बनाए, पर खुद शून्य बनी रहे। किसी भी कारण पति से उसका संबंध विच्छेद हो जाए तो उसके सारे अधिकारो पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज थोड़ी-बहुत स्थिति बदली जरूर है और महिलाएं अपने अधिकारो के प्रति सचेत हुई हैं तो कानून भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर स्थिति पूरी तरह बदल गई हो, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योंकि महिलाओं पर दहेज और अन्य कारणो से बढ़ते हुए जुल्म और अत्याचारो के आंकड़े पुरानी कहानी को ही नए ढंग से बयां करते नजर आते हैं। सन् 2000 मे दुनिया की स्त्रियो की प्रगति पर जारी रिपोर्ट कहती है, मैं उद्धृत करना चाहूंगी " हम लोगों को अपना रास्ता तो मालूम है, लेकिन हमने यह ध्यान नही रखा है कि इस रास्ते पर कितना आगे बढे हैं और हमे कितनी दूर और जाना है।"

माननीय उपसभापति महोदया, भारत में यह एक निश्चित कानून भी है कि पत्नी आग्रह कर सकती है कि उसे अपने पति के रिश्तेदारो के कारण होने वाले कष्टों से दूर रखा जाए तथा कि उसका अपने पति के साथ एकांत मे रहने का उचित प्रबन्ध किया जाए। रहने के स्थान का निर्णय दोनो की सहमति से किया जाए। किंतु प्रायः संयुक्त परिवारों में स्त्री पर ही सारे दोष थोप दिए जाते हैं और विवाह अनेक कारणों से टूटने के कगार पर आ जाते हैं और किसी भी रूप मे उसे बचाया जाना संभव नही हो पाता। ऐसे में जब तलाक जरूरी हो जाता है, तो ये जो संशोधन लाए गए हैं, वे पत्नी के हित में होगे, इसलिए निस्संदेह सराहनीय हैं। मैं एक बार और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक कंप्रीहैंसिव बिल लाएं, जिसमें डोमेस्टिक वायलैंस पर भी पूरी तरह रोक लग सके। मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंप्लसरी हो और महिलाओं को विवाह के बाद अपने पति की सम्पत्ति मे खास कर रहने के स्थान पर उसका भी अपना अधिकार हो। आज तलाक को लेकर लोगों में पूर्वाग्रह ज्यो का त्यो बना हुआ है। स्त्री को ही संदेह के घेरे मे लिया जाता है। न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन उसके लिए जटिल और दुरूह है, जो दूभर भी हो जाता है। यह संशोधन कुछ राहत दिलाएगा और वह जहां रहेगी वहां से अपना मुकदमा दायर कर सकेगी। अगर यह व्यवस्था हो जाए कि जब तक मुकदमा चलता है तब तक वह पति के घर में ही रह सके और सुरक्षित रूप से रह सके तो शायद इससे और भी अधिक सहूलियत होगी क्योकि कोई भी हिंदुस्तानी पत्नी जब तक उसका वश चलता है तब तक अपना घर छोड़ना नहीं चाहती क्योकि उसे तो यही शिक्षा मिली होती है।

**उपसभापति** : जी, उसको शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारी उस घर मे डोली जा रही है, अब तुम्हारी अर्थी ही वहां से निकलेगी।

**श्रीमती चन्द्रकला पांडे** : जी, मैडम, यही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारी डोली जा रही है, अब वहां से तुम्हारी अर्थी ही आए। मैं यहां पर रघुवीर सहाय जी को उद्धृत करना चाहूंगी -

पढ़िए गीता, बनिए सीता ।
फिर इन सबको लगा पलीता ।
निज घर-बार बसाए रखिए।
होए कटीली, आंखे गीली, तबियत ढीली।
घर की सबसे बड़ी पतीली ।
भरकर भात बनाइए।
रोते रहिए, घर न छोड़िए।

मैडम, जब जुल्म की अति हो जाती है तभी वह मुक्ति चाहती है। पत्नियो को यह सुविधा होनी चाहिए कि वह उस जुल्म से निवृत्ति पा सके और पतियों को यह सुविधा नही होनी चाहिए कि बात-बात पर तलाक देने की वे धमकी दे और 30 दिन में ही वे अपनी मर्जी कर ले। इसलिए यह जो 90 दिन का संशोधन विधेयक है, अच्छा है।

मैडम, अंत मे मैं यह कहना चाहूंगी कि तलाक प्रक्रिया को भी सरल और कम खर्चीला बनाने की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद ।

**उपसभापति** : श्री पी.जी.नारायणन।

**श्री बालकवि बैरागी** : मैडम, मुझे सिर्फ इतना कहना है।

**उपसभापति** : नारायणन साहब बोल रहे हैं, आप कहां से बीच मे खड़े हो गए।

**श्री बालकवि बैरागी** : मैडम, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अभी माया सिंह जी ने उदाहरण दिया। उन्होने कहा कि ग्वालियर की रहने वाली लड़की की शादी कोलकाता मे हो और चली जाए बंगलौर मे। मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि ग्वालियर वाली बोल चुकी, कोलकाता वाली बोल चुकी और बंगलौर वाली बोल चुकी है। अब क्यो आप परेशान हो रही हैं? ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति** : हम लोग चेन्नई ले जा रहे हैं क्योंकि वहां एक महिला का राज है।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Madam, the aim of the amendment is to make the process very simple. As per the present provision, the aggrieved woman has to file her petition in the court where her marriage was solemnised, is not considered adequate and fair. According to the present provision, the woman has to travel long distances to file her petition. Just to facilitate the woman to file her petition in the court where she is residing, for this purpose, this amendment has been brought forward. So, the aim of the Bill is to give rights to women. In my State, our Chief Minister, my leader, Dr. Puratchi Thalaivi is not only giving rights to women but also giving them important positions in all the fields. So, I support this Bill.

Madam, in the Bill, one correction has to be made. No district court exercises its original jurisdiction in respect of marriages. The only exception is the Christian marriages, which come under the Indian Divorce Act. So, I want the hon. Minister to bring forward a comprehensive Bill to include Christian marriages also.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala) : How can it be? ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry) : The Christian marriages are also tried by district courts. But.... ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: So, I support this Bill, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri C.P. Thirunavukkarasu.

SHRI N. JOTHI: The difficult man has got difficult name.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Madam, as the Law Minister has put it, it is CPT. I congratulate the Law Minister for bringing forward several Bills, like one -- as the financial burden on the woman was unlimited, he has brought forward amendment in the Special Marriage Act earlier. This is a landmark amendment Bill.

Madam, I would say that the purpose of bringing forward this Bill is, these provisions of the Act are not considered adequate or fair, as far as women are concerned. My submission is, if you look into the provisions of the Act, it gives the jurisdiction where the marriage is solmenised, where the

respondent is residing or the parties last resided; the fourth category is not essential. My submission in this regard is, if a husband files an application where the marriage was solemnised, or, if he files the application where both of them last resided, it is possible that the wife may be living at a place far away from these two places at the time of the application; then, the wife will be dragged on unnecessarily because of the filing of the application. I can see a number of applications for divorce, judicial separation, restoration of conjugal rights, etc. having filed by husband in different courts. In all these cases, the lady would be dragged on to the places where the marriage was solemnised or to the place where both resided last. In order to put an end to all these problems, the best thing is not to have these two clauses. Have only one clause to say, "Where the wife is residing" and the application can be filed either by the husband or wife.

Since you want to give the benefit to the lady, why do you have these two clauses by which she would be put to unnecessary hardship? She will be unnecessarily dragged to several places. This may kindly be considered by the hon. Minister.

Finally I would like to say one more thing. Now, the whole matter has been transferred from the district courts to the family courts. The district courts and the subordinate courts are not trying these matters now. But the family courts have been burdened with the cases relating to the Special Marriages Act, Hindu Adoption and Maintenance Act, the Christian Marriage Act and other Acts. So, there are a lot of cases pending before family courts. It may surprise you that there is only one family court judge appointed for the whole of a district. These judges are suffering like anything in order to dispose of the cases. Because of this heavy load, the speedy justice is not available in marriage-related cases. This too may kindly be considered by the hon. Minister. Thank you.

**डा0 कुमकुम राय** (बिहार) : धन्यवाद उपसभापति महोदया। काश आज हम लोग महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के लिए यहां इकट्ठे होते और उसके समर्थन मे मुझे बोलने का मौका मिला होता ...

**उपसभापति** : मिलेगा।

**डा0 कुमकुम राय** : क्योंकि यदि महिला आरक्षण बिल बन गया होता तो ये छोटी-मोटी बातों के अतिरिक्त बहुत बड़ी-बड़ी बाते हुआ करती और देश मे महिलाओ के शोषण और उनकी तकलीफो को कम करने के लिए यह छोटी-सी अमेंडमेंट लाने की जहमत ही नही उठानी पड़ती।

**उपसभापति** : एक तरह से यह भी आरक्षण नहीं तो रक्षण तो है।

**डा0 कुमकुम राय** : इसीलिए चूंकि रक्षक हैं इसलिए इस विधि मे इन्हे दिखाई पड़ा और जैसाकि महिला आयोग और विधि आयोग ने भी अनुशंसा की थी, इसीलिए विवाह विधि (संशोधन) विधेयक लाया गया है। जैसाकि हमारे पूर्ववक्ताओ ने कहा कि इससे पहले जो पीड़ित और दुखी महिलाएं विवाह विच्छेद के लिए तैयार हुआ करती थी, वे तमाम दुख-तकलीफो, परेशानियो और मुश्किलात का सामना करती थी। जनरली यह हुआ करता था कि जहां पति का आवास या पति का घर हुआ करता था, वहां पर तो उसका इतना प्रभाव हुआ करता था कि उसके परियार के लोग या उनके प्रभाव क्षेत्र मे आने वाले लोगो के कारण वह उस शहर या मोहल्ले तक में जाना पसंद नही किया करती थी। ऐसी हालत मे वह कोर्ट मे जाकर अपना केस और अपनी तमाम शिकायतो को दर्ज करा सके और न्याय से संरक्षण प्राप्त कर सके तथा न्यायालय के आदेश के माध्यम से उसको कुछ सुविधा मिल सके, इन सारी प्रक्रियाओ मे उसे बहुत मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन इस विधेयक मे यह जो संशोधन होगा और इसमे यदि यह हो जाए कि उसे जहां सुविधा हो वहीं वह इस प्रकार का केस कर सके तो यह स्वागत योग्य होगा। अब तो जरूरी नही है कि वह मायके मे ही जाकर रहे। आज महिलाएं पढ़-लिख रही हैं और अपने पैरो पर खड़ी भी हो रही हैं। इसलिए उसको जहां सुविधा हो - जिस जिले मे, शहर मे वह काम कर रही हो, बाद मे जाकर रह रही हो, उसे जहां सुविधा हो वही पर अगर वह इस प्रकार का केस कर सके और न्यायिक संरक्षण के लिए अपील कर सके, यदि इस कानून मे इस प्रकार का प्रावधान हो तो यह और ज्यादा स्वागत योग्य बन सकेगा।

इसके दूसरे उपबंध मे जो अमेंडमेंट की बात की गई है, यह वास्तव मे कुछ ज्यादा स्वागत योग्य बन पड़ा है क्योकि उच्च न्यायालय या अपर कोर्ट मे अपील करने की जो 30 दिन की समयावधि थी, वह वास्तव मे बहुत कम थी क्योंकि इस पुरुषवादी समाज मे पुरुषो के तमाम हथकंडे ऐसे हैं जिनसे औरतो को कदम-कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति मे विवाह विच्छेद के समय कोर्ट से decree प्राप्त करने के बाद 30 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नही लगता। उस केस को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं जिसके लिए 30 दिन की अवधि बहुत कम हुआ करती है। अब हमारे विधि मंत्री जी ने 30 दिन की अवधि को 90 दिन किया है। इससे उन्हे काफी सुविधा प्राप्त हो जाएगी और वे संबंधित कागज़ातो और पैसे इत्यादि का इंतजाम करके अपने मुकदमे को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय मे ले जा सकती हैं। इसलिए इन दोनो प्रावधानो मे जो परिवर्तन किया गया है, जो संशोधन किया गया है, मैं इनका तहेदिल से स्वागत और समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Madam Deputy Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak. Madam, I welcome the Marriage Laws (Amendment) Bill, 2003. The main feature of

this Bill is that it gives a right to the petitioner, that is, a woman to file an petition where she resides. Earlier the time given was 30 days. Now, it has been increased to 90 days. Today the sanctity of marriage concept is different from what it was 15 years ago in a sense that earlier talking about divorce was thought to be a sin. Now some people are saying that in certain circumstances it has become necessary. Sometimes a divorce is taken for welfare. So, this is the case. This Bill intends to give a right to the women. In the meantime, I would request the hon. Minister to get those cases expedited which are pending for more than four or five years due to heavy work. They are not being decided. The speed, which is required for disposing of these cases, that is not there. I am submitting it because all the family courts are set up at district headquarters or in the metropolitan cities. A few Family Courts are also set up in some cities. I would like to submit to the hon. Minister that in Courts, the women even with one or two children wait from 11 o' clock in the morning till 5 o' clock in the evening at the doors of the courts. The cases are not being decided for four years, five years or six years. Actually, it is a crime. I would request the hon. Minister to see that such cases are expedited. As far as divorce is concerned, there are both illiterate and literate persons. Among the illiterate, there is not a much high percentage of divorce. Either it is a man or a woman it makes no difference. For that purpose, I would like to submit that divorce procedure has to be simplified. If any educated wife and husband are ready for divorce mutually, even in that case also they will have to wait for six months for filing a petition. After that, there is conciliation and in one way or the other, it takes a lot of time. In the case of educated persons, why should we halt their immediate separation? The scenario has changed now. For that reason, I can understand the concept of the society also. As far as divorce is concerned, the matter has to be simplified and is settled as early as possible. With these words, I support this Bill.

**श्री बालकवि बैरागी** : महोदया, जेटली साहब बोले, इससे पहले दो पंक्तियां इसमे जरूर डाल दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी। वक्त निकल गया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं -

"बिना तुम्हारे मुझको खुद से डर लगता है,
तुम होती हो तो घर सचमुच घर लगता है।"

मैडम, ऐसे मे ये काहे तलाक की बात कर रहे हैं? जो कुछ कानून बनाना है, जल्दी पास कर दो। बहुत अच्छा बिल लाने के लिए मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान करे यह शब्द ही हिंदुस्तान से चला जाए।

**उपसभापति** : बालकवि बैरागी जी की क्या परिस्थिति है इस सिलसिले में।

**श्री बालकवि बैरागी** : मैडम, परिस्थिति यह है कि हम सचमुच में आपसे कहे कि यह मुल्क कोई अकेले रहने का मुल्क नहीं है, यह तो सबके साथ मिलकर रहने का मुल्क है।

**मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी** (मध्य प्रदेश) : मैडम, औरत के अहसास के मुताल्लिक और इस तलाक की पीड़ा से मुताल्लिक एक बात मैं भी कहना चाहूंगा मंत्री जी के बयान से पहले।

"तलाक दे तो रहे हो, जला दो कहर के साथ,
मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ।"

**उपसभापति** : मंत्री जी, ऐसे बिल बार-बार लाया करिए जिससे लोगों को काफी इंसपिरेशन आता है बोलने का।

**श्री बालकवि बैरागी** : यह तो शबाब का "श" भी नहीं लौटाएंगे।

**मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी** : नहीं, शबाब तो आप नहीं लौटाएंगे, आप उसका हक लौटाइए।

**उपसभापति** : वह विचार होने पर यह हरकत की नहीं है, तो उन पर यह लागू नहीं होता।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, several hon. Members have expressed their opinion, all in support of this Bill. Let me clarify, at the very outset, that the object of this Bill, as one of the hon. Members obliquely indicated, is not to encourage divorces. Broken marriages and divorces have several adverse human consequences. They can create emotional distress. They can create social distress. They can affect the social fabric of the society. If, today, we see in the West, particularly the developed countries, where the rate of divorces and breaking up of marriage is very high, there are countries where the depression rate is very high. There are countries where the suicide rate is very high. And, one of the reasons for demographic change is because a number of marriages are breaking up. The countries where this is happening, where the number of working hands and knowledge minds available, really to discharge the functions within their growing economies, is not adequate in itself. So, this is a larger social and economic impact which has been

created. So, the object, certainly, is not to encourage divorces. But the object of this Bill, as also several other legislations that the Government has proposed during the last few years, is, really, that whatever inequities have existed in the laws relating to marriages and divorces and various personal laws, with the participation and consent of the communities and their leaders, and opinion-makers of those communities, we must try and see to it that these inequities in themselves are removed. And, slowly, but surely, we have been moving in that direction. An hon. Member mentioned that we must now have procedures under the Christian Law to be simplified. I must refresh the hon. Member's memory that during the last fifty years, at least, three attempts were made earlier to correct what were considered by many as some aberrations in the Christian law. The man and woman in their rights were considered to be different. The procedures are very cumbersome, because Christianity, as a religion, abhor the idea of divorce. They felt marriages are an institution that cannot be ended in itself. There was, from several sections of the community, a considerable opposition. But, two years ago, when we did make certain proposals, with regard to amendments to the Christian Laws, there was, initially, a discussion amongst the members of the community and, finally, the leaders of the community insisted and, two years ago, the Indian Divorce Act was amended and several provisions of the Indian Divorce Act, which created inequities in themselves, were removed from the provisions of the Indian Divorce Act. So, that amendment has already taken place. Madam, people, have now, no longer need to go to the High Court for confirmation of divorces. Now, the grounds of divorce available to a man and a woman are identical. Various parities have been restored and inequities in such have been removed.

Now, I come to maintenance laws. We have amended Section 125 of the Cr.P.C. We have removed upper cap of Rs. 500. We have amended various other personal laws, including the Special Marriage Act, the Hindu Marriage Act, the Christian Marriage Act where we have made provisions for payment of maintenance far simpler. Now, these are the various provisions which we have amended in various laws over the last few years and this amendment is also pursuant to the direction which we have been, slowly, following. Now, the reasons which have necessitated these two amendments are: The first one is in relation to the jurisdiction of a court where a petition can be filed in relation to any of the matrimonial causes of action. I would beg to humbly disagree with the hon. Member when he

said that some provisions of jurisdiction could be removed. One of the provisions was, where the marriage had been solemnised, is the court of appropriate jurisdiction; where the parties last resided, is the court of appropriate jurisdiction; where the respondent, against whom the action is maintained, is the court of appropriate jurisdiction. These were all considered appropriate courts, and are still considered appropriate courts because if a case is contested, then, it is not the interest of the man and the woman which alone is the cause of justice; the object of the judge would be to find out who has committed the matrimonial wrong. Therefore, those would be the appropriate courts, within whose jurisdiction the evidence of that matrimonial wrong would be available. So, if the party has last resided in Bangalore, and the case is transferred, let us say, to Shimla, then every witness will have to travel from Bangalore to Shimla and, therefore, to say that Bangalore should never have the jurisdiction in itself, may itself create an inequity. That is not one of the objects, as far as the Government is concerned, behind proposing this. The real object is that, with these jurisdictions intact, if a wife presents a petition, she should, having gone away from her matrimonial home to some other place, or her parents home, or to some relatives home, be entitled, because she is the one who really has been, in a broken marriage, more at the receiving end. Most of the Indian women even today are not earning. They have to depend on relatives or parents, in a broken marriage, for their livelihood. Their ability to travel long distances on every date of hearing and contest the case is very limited. Therefore, it is an enabling provision, which gives to the woman in a broken marriage, the right to present a petition in a court within whose jurisdiction she is residing after the broken marriage. It is an enabling provision, which provides further facility to the women. This would be of considerable use, as far as women are concerned.

I am extremely grateful to the hon. Member, Shrimati Bimba Raikar, who had initially suggested it to be brought forward as a Private Member's Bill. The Women's Commission had supported this idea. The Law Commission had supported this idea. Therefore, this is a proposal, which is really a beneficial proposal for women, which has received support all along.

As far as the second provision, in relation to the enlargement of time for filing an appeal, is concerned, this has one more object, besides the objects which the hon. Members had pleaded. In a number of matrimonial cases, thirty days' time is being given, the woman being

inadequate in her resources at times, is not able to contest. Cases have also come to notice, where *ex parte* orders are obtained, and once, *ex parte* orders are obtained, by either not serving the woman, or, by giving a wrong address, and after the *ex parte* decree, if within thirty days no appeal is filed, the man marries once again. And once the woman realises that there is a new family which has come into existence -- there are hundreds and thousands of cases all over the country -- it is then that she realises that a divorce has been procured behind her back. When she goes back to the court, she is told that thirty days' period is over, and she is unable to file the appeal. Now, in case this divorce is set aside, questions have arisen as to what would happen to the second marriage, what would happen to the children born out of the second marriage, and this would create further complications. As a result of this, the Supreme Court itself, in one of the judgments, has suggested that, at least, to bring some end to this practice, if not entirely, we should enlarge the period, as far as the filing of the appeal is concerned. Therefore, for people who are victims of *ex parte* orders, particularly which are obtained behind their back, or, people who may have to raise resources in order to file an appeal, because appeals in a divorce case would lie to the High Court, from a moffusil court or from a district court, somebody would have to travel to the State Capital to go to the High Court, resources would be required, women are inadequate in their resources; so, 30 days itself is an inadequate period. This period should be extended to 90 days. This was the purpose behind the suggestion. Therefore, I am extremely obliged to the hon. Members, who have supported this particular suggestion of enhancing this period. Yes, it is very right, what the Hon. Member, Mr. Gowda, pointed out that something has to be done in order to improve the efficiency of the courts, where these cases are being heard. The Act itself mentions that a divorce case should normally get over in six months to one year. That should be the normal period. But because of the workload of the courts, and the inadequate infrastructure in the courts, all across the country, this, at times, takes a lot of time. Now, this time period itself causes a lot of distress because if years and years altogether, and literally decades are spent between the original cases and also the appeals, people, besides being harassed emotionally, are gaining in years.... people are gaining in years, people are gaining in age. So, the prospects of settling in life after the divorce also get diluted or diminished. And, therefore, this adds to the distress. In fact, distress becomes destitution in some cases because such may be the adverse consequences of delays in these cases. Therefore, we have been

suggesting to all the States where family courts have not been set up -- a large number of States have set them up -- that family courts must be encouraged so that these could be settled through a procedure which is not strictly bound by the Civil Procedure. These should be quickly settled. In fact, one of the steps which I had taken last month -- I had already informed this House in another context -- was about other offences against women. We have now written to the Chief Ministers, and the Chief Justices of all High Courts that cases of offence against women along with cases of senior citizens should all be also transferred to the fast track courts which were disposing of only sessions cases, so that these cases also could be expeditiously disposed of. This, Madam, being the objective of this particular amendment, I am extremely grateful to the hon. Members who have supported it. I commend to this hon. House that this amendment be accepted..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. When are you bringing the Atrocities Against the Women (Amendment) Bill and the Domestic Violence Bill?

SHRI ARUN JAITLEY: The Domestic Violence Bill has already been introduced in this House. I think it is pending before the Standing Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is a very important Bill. Not only is there domestic violence, but there is campus violence and street violence also. The cases of violence against women are on the increase, especially, in metropolitan cities. The question is:

> "That the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954 and the Hindu Marriage Act, 1955, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 6 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I move :

That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

**Re. MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is a statement by Mr. George Fernandes. ...*(Interruptions)*...

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, यह जो Merchant Shipping (Amendment) Bill है। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति** : कर रहे हैं।

**श्री राजू परमार** (गुजरात) : मैडम, Merchant Shipping (Amendment) Bill कहां गया?...**(व्यवधान)**... मिनिस्टर साहब अभी यहां बैठे थे।...**(व्यवधान)**... यह क्या बात है? ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति** : वह हो जाएगा। आप यहां बैठिए, मैं वह भी करा दूंगी।

**श्री सुरेश पचौरी** : इससे पहले राजनाथ सिंह जी का...**(व्यवधान)**...

**श्री राजू परमार** : लिस्टिड बिज़िनेस में पहले है। अभी मिनिस्टर आकर चले गए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री एस0 एस0 अहलुवालिया** (झारखंड) : अखनूर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : अगर आप इतने चिंतित थे तो यह लिस्ट में पहले रखना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala) : This is also very important. ...*(Interruptions)*...

**श्री राजू परमार** : शत्रुघ्न सिन्हा जी आकर चले गए। ...**(व्यवधान)**...